

अजीब सी शान्ति है, भारत के टॉप अरबपतियों में

दशकों की मेहनत व भाग्य से निर्मित उनके साम्राज्य तिलमिला गये, ट्रम्प के टैरिफ वॉर से उभरी अस्थिरता से

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 14 अप्रैल। यह साल गायब होते अरबपतियों का रहा है। दशकों की मेहनत से बनाई गई संपत्तियाँ कुछ ही महीनों में धराशायी हो गई हैं। भारत के अभिजात्य वर्ग के बिज़नेस गलियारों, जो एक समय पर वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से भरे थे, तथा जहाँ बिज़नेस एक्सपैन्शन की बातें होती थीं, वहाँ अब खोई हुई संपत्ति की बैचैन खामोशी गूँज रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक परिस्थितियों बिगड़ों और बाज़ार अनिश्चितता के बोझ के नीचे दब गए, तो भारत के सबसे अमीर लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्हें न तो उम्मीद थी और न ही जिससे वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सन् 2025 के पहले कुछ महीनों में ही भारत के सबसे अमीर बिज़नेस लीडर्स की संयुक्त संपत्ति में 30.5 अरब (2.63 लाख करोड़) डॉलर की भारी गिरावट आई है। संपत्ति में यह भारी गिरावट, भारतीय शेयर बाज़ारों में तेज़ गिरावट के बीच आई है, जिसकी शुरुआत हुई विदेशी निवेशकों द्वारा अपना पैसा बाज़ार से

- टॉप अरबपतियों की "वैल्यू" को 30.5 बिलियन डॉलर यानी 2.63 लाख करोड़ रुपये का झटका लगा है।
- सबसे बड़ा झटका हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड (एचसीएल) के मालिक व संस्थापक शिव नाडर को लगा, जिनकी वैल्यू 10.5 बिलियन डॉलर गिरी। यह सच है कि ग्लोबल स्टोडाउन में सबसे बड़ा झटका आईटी सैक्टर को लगा है, पर, शिव नाडर को हुए नुकसान से तो लगता है, इस अनिश्चितता की सारी मार शिव नाडर की कम्पनियों पर आई है।
- मुकेश अंबानी की सम्पदा पर भी 3.42 डॉलर की मार आई, एशिया में सबसे अमीर मुकेश अंबानी, जो विश्व के सबसे अमीरों की लिस्ट में ऊपर रहते आए हैं, पर, अब वे लुढ़क कर विश्व के सबसे समृद्धों की सूची में 17वें नम्बर पर आ गये हैं। उनकी फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इण्डस्ट्रीज़ को इतना भारी नुकसान नहीं हुआ, पर, उनकी दूसरी बड़ी कंपनी जियो फायनॅशियल सर्विसेज़ की "वैल्यू" 24 प्रतिशत घटी।
- अडानी ग्रुप की कंपनियों की "नेटवर्थ" 6.05 बिलियन डॉलर की कमी आई तथा अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एन्टरप्राइजेज की वैल्यू 9 प्रतिशत घटी।
- जिंदल ग्रुप की मुखिया, सावित्री जिंदल को भी झटका लगा, उनकी कंपनी की वैल्यू में 2.4 बिलियन डॉलर का नुकसान आका जा रहा है।
- सन फार्मा के मालिक दिलीप संधवी ने भी वर्तमान इकोनॉमिक उथल-पुथल में 3.4 बिलियन डॉलर खोये।
- नुकसान साधारण इन्वेस्टर को भी हुआ है तथा सैंसेक्स व निफ्टी में 4.5 प्रतिशत की टूट आयी है, विशेषकर मध्यम श्रेणी व लघु श्रेणी की कंपनियों में 14 प्रतिशत व 17 प्रतिशत टूट हुई शेर की कीमतों में।

निकालने के कारण। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर ट्रेड को लेकर बढ़ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रामविलास पासवान के भाई व केन्द्रीय मंत्री रहे पारस ने एनडीए से नाता तोड़ा

—श्रीनन्द झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 14 अप्रैल। इस वर्ष के अन्त में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य में राजनैतिक समीकरणों में भारी उलटफेर होना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत करते हुये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए छोड़ दिया है।

उन्होंने संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने के मामले में गुमहमती अमित शाह का नाम लिया, साथ ही यह भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने "दलित - केन्द्रित पार्टी" होने के नाते, आरएलजेपी की उपेक्षा की तथा उसका अपमान किया।

भाजपा द्वारा एलजेपी के पारस गुट के मुकाबले, पासवान के बेटे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट को खड़ा करने के कारण, पारस का एनडीए से सम्बंध विच्छेद अपेक्षित ही था।

जहाँ एलजेपी के संस्थापक राम विलास पासवान की मृत्यु के बाद, भाजपा पारस गुट के पक्ष में थी तथा उसने पारस को केन्द्रीय मंत्री तक बना दिया था, वहीं, लोकसभा चुनावों से पहले स्थितियों पूरी तरह उलट गई तथा भाजपा ने चिराग गुट को अपने साथ ले लिया, तथा पारस के साथ सीट-शेयरिंग से साफ इनकार कर दिया, जबकि आरएलजेपी के 17 वीं लोकसभा में 5 सांसद थे। पारस ने कहा, "हमने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन एनडीए ने हमारा परिवार्यग कर दिया। उस समय

यह स्पष्ट हुआ कि हमारी उपेक्षा दलित-केन्द्रित पार्टी होने के कारण की जा रही है।" पारस ने आगे कहा, "संभवतः भाजपा दलित-विरोधी है।

पारस ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद, उन्हें गठबंधन नेताओं की प्रमुख मीटिंगों से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा, "भाजपा और जेडीयू का मानना है कि बिहार में एनडीए के केवल 5 घटक दल हैं। एनडीए के घटक दल के रूप में मेरी पार्टी का नाम भी नहीं लिया गया।"

हालाँकि पारस ने अपनी भविष्य की योजना नहीं बताई, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं कि उनका रुख

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट के दखल पर सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति मिली

जयपुर, 14 अप्रैल। सफाई कर्मचारी-2018 में नियुक्ति से वंचित किए गए अर्थाथियों को राजस्थान हाईकोर्ट के दखल के बाद राहत मिली है। अदालत में याचिका दायर होने के बाद दिए निर्देश को लेकर विभाग ने याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति मिलने पर अदालत ने मामले

अतिरिक्त महाधिवक्ता गिल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के कार्यग्रहण के आदेश जारी हो चुके हैं।

में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश हेमराज मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जोएस गिल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को सफाई कर्मचारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य सरकार मैडिकल कॉलेजों के रिक्त पद भरने की योजना बनाये

जयपुर, 14 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में यह बताने को कहा है कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की क्या कार्य योजना है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि यदि किसी प्रकरण में अदालत की ओर से नियुक्ति पर रोक है तो उसकी अलग से स्पष्ट जानकारी दी जाए। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश महेंद्र गौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित में है कि मैडिकल कॉलेजों के सभी संकाय भरे जाएं।

कि यह वास्तव में जनहित में है कि मेडिकल कॉलेजों में सभी संकाय भरे जाएं और शिक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सुनवाई के दौरान, अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र में बताया गया कि प्रदेश में संचालित निजी मेडिकल कॉलेजों में खाली पद लगभग शून्य हैं। वहीं, राज्य सरकार और स्वायत्तशासी संस्थाओं की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्टालिन उत्साहित: वाइस चांसलरों की मीटिंग बुलाई

मीटिंग के मार्फत स्टालिन अब उन निर्णयों को उखाड़ना शुरू करेंगे, जो राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के चांसलर की हैसियत से लिये थे

—लक्ष्मण बैंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 14 अप्रैल। राज्यपाल से चली लम्बी लड़ाई के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को अब उनसे बहला लेने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई करने का अवसर मिल गया है। इन संस्थाओं का राज्यपाल ने कुलाधिपति की हैसियत से भगवाकरण किया था।

मुख्यमंत्री ने उस नुकसान को भरपाई की शुरुआत करते हुये, बुधवार को सभी विश्वविद्यालयों के सभी उपकुलपतियों तथा रजिस्ट्रारों की एक मीटिंग राज्य सचिवालय में बुलाई है। अब इस अधिकार से वंचित हो जाने के बाद, राज्यपाल ठाले-बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते।

स्टालिन ने कहा कि विश्वविद्यालयों के चांसलर होने की हैसियत से, राज्यपाल का लक्ष्य राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के की प्रतिष्ठा को चूर-चूर कर देना था तथा उन्होंने उच्च शिक्षा का भगवाकरण करके अनैतिकतापूर्ण राजनीति स्थापित कर दी

स्टालिन के अनुसार, वे तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों का भगवाकरण खत्म करेंगे, जो राज्यपाल आर.एन. रवि, ने विश्वविद्यालयों के चांसलर की भूमिका में शुरू कर रखा था।

उदाहरण के लिये, राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्तियों की थीं।

राज्यपाल आर.एन. रवि ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भारी जोर दिया था तथा नई नीति को क्रांतिकारी व बदलाव लाने वाली नीति बताया करते थे। पर, अब तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जो प्रदेश की शिक्षा नीति का नया ड्राफ्ट तैयार करेगी।

थी। स्टालिन ने इसके विरुद्ध विधानसभा में विधेयक पारित कराये थे। आशा की जा रही है कि परामर्श के लिये बुधवार को होने वाली इस मीटिंग में, उच्च शिक्षण संस्थानों को भगवाकरण से मुक्त करने की प्रक्रिया की नींव रख दी जायेगी तथा राज्यपाल के आदेश पर हुई नियुक्तियों को रद्द किये जाने की संभावनाएं हैं।

सोमवार को राज्य सरकार द्वारा

जारी की गई एक सरकारी विज्ञापित में कहा गया है कि बुधवार की मीटिंग का एजेंडा राज्य की उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिये है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिये थे कि विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न विधेयक, जो विधानसभा ने दोबारा भेजे हैं तथा राष्ट्रपति के पास लम्बित हैं, राष्ट्रपति की सहमति-प्राप्त माने जायेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन ने अमेरिका पर पलटवार किया

अमेरिका को "रेअर अर्थ" खनिज व कैमिकल्स की सप्लाई भेजना स्थगित किया

"रेअर अर्थ" 17 खनिजों का समूह है, जो रक्षा, इलैक्ट्रिक वाहन, एनर्जी व इलैक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्री में अति महत्वपूर्ण हैं और इनका कोई विकल्प नहीं है।

चीन इन "रेअर अर्थ" मिनरल्स को निर्यात करने के लिये "रेग्युलेटरी व्यवस्था" विकसित कर रहा है। निर्यात करने के लिये लायसेंस जारी करेगा तथा बाद में इन मिनरल्स के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिये, कभी लायसेंस जारी करने कमी करके अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से संबंध उद्योगों, नई टेक्नोलॉजी, जैसे इलैक्ट्रिक कार, आदि प्रोडक्ट बनाने वाली बड़ी कंपनियों का गला घोट सकता।

निर्यात पर रोक लगाना टुंग के टैरिफ वॉर पर चीन का जवाब है। चीन के इस कदम का लक्ष्य अमेरिका की कमजोरी पर वार करना है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व पर चीन का एकाधिकार सा है। विश्व के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का लगभग 90 प्रतिशत चीन के पास है। रक्षा, इलैक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और इलैक्ट्रॉनिक्स में काम

आने वाले 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व चीन में ही मिलते हैं।

सात श्रेणी के मध्यम एवं भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों -सैमेरियम गंडोलिनियम, टरवियम, डाइप्रोसियम, लुटेरियम, स्कैंडियम और यट्रियम को निर्यात निर्यंत्रण सूची में शामिल किया गया। अमेरिका पास

दुर्लभ पृथ्वी तत्व को मात्र एक खान है और दुर्लभ खनिज की अधिकांश आपूर्ति यह चीन से करता है।

बीजिंग ने 2 अप्रैल को पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि चीन पर टैरिफ बढ़ाने के टुंग के निर्णय के जवाब में उठाया गया चीन का कदम था। टुंग ने चीन के सामान पर तब 54 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, न केवल खनिजों, बल्कि चुंबक और अन्य तैयार सामान के निर्यात पर जो निर्यंत्रण लगाया गया है, उसे बदलना काफी मुश्किल है।

बीजिंग लम्बे समय से इसका संकेत दे रहा था और इस कदम से अमेरिका व चीन में तनाव और बढ़ सकता है और अमेरिकन कम्पनियों, जो दशकों से अपने उत्पादन के लिए इन तत्वों पर निर्भर हैं, वे भारी संकट में पड़ सकती हैं।

इन खनिजों और विशेष चुंबकों को विशेष निर्यात लाइसेंस के बाद ही बाहर भेजा जा सकता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राम मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना

अयोध्या, 14 अप्रैल। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर में सोमवार को ब्राह्मणों की उपस्थिति में वैदिक विधि-विधान के साथ मुख्य शिखर पर कलश स्थापित किया गया। यह पवित्र कार्य सुबह 9:15 बजे शुरू हुआ और 10:30 बजे शिखर पर कलश की स्थापना पूरी हुई। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने

सुबह सवा नौ बजे से 10.50 के बीच विधिविधान से कलश स्थापना की गई।

बताया कि वैशाखी और बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्य संपन्न हुआ। अब मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजदंड स्थापना की प्रक्रिया शुरू होगी। मंदिर निर्माण प्रगति पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)